



सच को बयां करती 'द कश्मीर फाइल्स'

डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर, तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' सभी की अन्तरात्मा को झकझोर देने वाली फिल्म है। शायद यही कारण है कि युवाओं के अलावा सिनेमा घर में शारीरिक रूप से अस्वस्थ ऐसे बहुत से वृद्ध भी देखने को मिले जो अपने घरवालों के साथ फिल्म को देखने आए थे। बीस-बाईस वर्ष के युवा इस फिल्म के माध्यम से न केवल जम्मू-कश्मीर वरन् भारत की तत्कालीन स्थिति तथा सरकार की कार्यप्रणाली से अवगत होने के लिए आए थे। यह सभी यह देखना व जानना चाहते थे कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था जोकि धनी व सम्पन्न होते हुए भी कश्मीर से विस्थापित हुए तथा अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर विवश हुए। सरकार ने कैसे कश्मीरी पंडितों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया।

वैसे तो कश्मीरी पंडितों पर पहले भी बहुत अत्याचार हुए थे परन्तु जनवरी 1990 में हुयी घटनाओं ने मानवता की सारी हदें तोड़ते हुए ऐसे अमानवीय कृत्य किये जिनको सुनकर आम आदमी का कलेजा कांप जाता है। जी हां, बात है 19 जनवरी 1990 की लेकिन 19 जनवरी को समझने के पहले हमें पूर्व के घटनाक्रम को समझना होगा। 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार हुयी तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार का गठन दिनांक 02 दिसम्बर 1989 को हुआ। 18 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने अपना त्यागपत्र दे दिया। जगमोहन जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके थे उन्हें पुनः स्थिति को संभालने के लिए जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्हें 19 जनवरी को श्रीनगर पहुंचना था लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे वहां पहुंच नहीं सके थे। फारूख अब्दुल्ला ने अपने त्यागपत्र से पहले गांवों से सीआरपीएफ हटा ली थी। इसलिए गांवों में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं



था। राज्यपाल भी श्रीनगर नहीं पहुंच सके थे। इसलिए सरकार नाम की कोई भी संस्था वहां नहीं थी।

हेता ठाकर तथा वैश्वनी मिश्रा ने अपने शोध पत्र में कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकारों ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की समस्या को ठीक प्रकार से हल करने के प्रयास नहीं किये। *सरकार ने आवश्यक कदम नहीं उठाए तथा साथ ही इतने जघन्य अपराध पर मीडिया ने भी समुचित कवरेज नहीं किया।*

'द काश्मीर फाइल्स' फिल्म में जिन दृष्यों को प्रमुखता से उभारा गया है इन पिछले बत्तीस वर्षों में उन घटनाओं को कितनी चालाकी से छिपाया गया वह अब सभी के सामने हैं। जैसा कि लेख के शुरुआत में ही इंगित किया है कि जम्मू कश्मीर में लगभग दो दिन सरकार ही अस्तित्व में नहीं थी तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भी गांव से हटा लिए गए थे। इसका लाभ उठाते हुए अलगाववादी आतंकवादियों ने दिनांक 19 जनवरी 1990 को रात्रि 9 बजे घाटी की मस्जिदों से लाउडस्पीकर लगाकर इस्लाम और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिये। कश्मीरी पंडितों से काश्मीर छोड़ने के नारे लगवाने लगे, उनसे कहा जाने लगा कि या तो मतान्तरण कर लो या कश्मीर छोड़ दो या मरने के लिए तैयार रहो (रैलिव, सैलिव या चैलिव)। आतंकी एकदम स्पष्ट उद्देश्य के साथ नारे लगा रहे थे कि काश्मीर को कश्मीरी पंडितों से खाली कराकर पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक कश्मीर बनाया जाए। वे नारे लगा रहे थे कि कश्मीरी पंडित अपनी स्त्रियों को छोड़कर यहां से चले जाएं या मरने के लिए तैयार रहें। बाजारों, कश्मीरी पंडितों के घरों के मुख्य द्वार पर और रास्तों पर कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य करते हुए उनके नाम चस्पा कर दिये गए। यह एक प्रकार से कश्मीरी पंडितों के लिए युद्ध की स्थिति थी जिसमें उन्हें या तो मरना था या बिना सामना किये अपना सब कुछ छोड़कर भागना था। पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तदनुसार 19 जनवरी 1990 की उस अंधेरी रात में हांड कंपकंपा देने वाली ठंड में काश्मीरी पंडितों ने जब अपने घरों से बाहर निकल कर देखा तो हतप्रभ रह गए। मुस्लिम अपने घरों से बिछाने के लिए दरी व अन्य सामान के साथ ही ठंड से बचने के लिए आग जलाने के लिए लकड़ी भी साथ लाए थे। वे



सड़कों पर नाच रहे थे, भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नारे बाजी की जा रही थी। कश्मीरी पंडितों ने जब अपने पड़ोसी मुस्लिमों को अपने ही खिलाफ जहर उगलते सुना तो उन्हें अपने कानों पर सहज विश्वास ही नहीं हुआ और पीढ़ियों का संबंध तुरंत तार-तार हो गया। पंडितों के सामने जान बचाने तथा घर की स्त्रियों व बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए वहां से पलायन करने के अलावा कोई और चारा न था। 20 जनवरी 1990 को पूरे शहर में पुलिस सड़कों से गायब थी। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। मस्जिदों के लाउडस्पीकर से पंडितों को घाटी छोड़ देने की चेतावनी दी जा रही थी, अन्यथा की स्थिति में जान और प्रतिष्ठा खोने का भय दिखाया जा रहा था। श्रीनगर से प्रकाशित होने वाले 'अलसफा' उर्दू दैनिक ने कश्मीरी पंडितों को सम्बोधित करते हुए लिखा था कि, 'यदि वे सम्मान सहित जीना चाहते हैं तो कुछ ही घण्टों में घाटी छोड़ दें।' घाटी की सड़कों पर भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़ते जा रहे थे। पंडितों को कहीं से भी सहायता की आशा नहीं बची थी। रेडियो कश्मीर ने भी सांय के बुलटिन में यह प्रसारित किया कि, 'कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने गोली मार दी।' कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गयी थी कि बलात्कार, लूट और हत्या आम बात हो गयी थी। कश्मीरी पंडितों की सुनने वाला कोई नहीं था। कुपवाड़ा जिले में सरकारी स्कूल में शिक्षिका गिरिजा टिक्कू अपना वेतन लेकर लौट रही थीं कुछ बंदूकधारियों ने उनका अपहरण कर लिया और सामूहिक बलात्कार करने के बाद उन्हें जीवित ही आरा मशीन से काट कर उनके शरीर के दो टुकड़े कर दिये। सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की क्रूरता और भयावहता सभी को झकझोर देने वाली है। खाद्य आपूर्ति विभाग के उप निदेशक अवतार सिंह कौल, श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक लस्सा कौल, अनंतनाग के पंडित प्रेम नाथ भट्ट, जम्मू कश्मीर सरकार के प्रतिष्ठित इतिहासकार प्रोफेसर नीलकंठ रैना (लाला) की गोली मार कर हत्या करने के साथ ही 4 मार्च 1990 को सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर की पत्नी श्रीमती एम एन पॉला अपहरण और सामूहिक बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गयी। मार्च 1990 में ही अपने को बचाने के लिए चावल भरे ड्रम में छिपे हुए दूरसंचार विभाग के इंजीनियर बी० के० गंजू की बुरी तरह गोली मारकर हत्या कर दी, वह जब उनकी पत्नी ने उन आतंकियों से कहा कि उन्हें भी



गोली मार दें क्योंकि वे अकेले कैसे रहेंगी? तो आतंकियों ने उत्तर दिया कि, 'कि 'किसी को इसकी लाश पर रोने के लिए भी तो होना चाहिए।' अप्रैल 1990 में नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर कई दिनों से बलात्कार किया जाता रहा उनका शव सड़क के किनारे मिला। मई 1990 में श्रीमती प्राना गंजू और उनके पति प्रोफेसर के एल गंजू का सोपौर में अपहरण कर लिया प्राना गंजू से बलात्कार करने के बाद दोनो पति और पत्नी की हत्या कर दी गयी। जून 1990 में श्रीमती जे एल गंजू उनके पति और नन्द की श्रीनगर स्थित बन मोहल्ला में घर पर हत्या कर दी गयी। श्रीनगर के अली कदल इलाके में तेजाधर तथा बाटामालू में नानाजी नामक महिलाओं की हत्या कर दी गयी। जुलाई 1990 में डॉ० साहनी को श्रीनगर के करन नगर इलाके में उनके घर में बंद कर आग लगा दी गयी और उन्हें जिन्दा जला दिया गया। अगस्त 1990 में बबली रैना का घरवालों के सामने बलात्कार कर गोली मार दी गयी। सहिष्णुता, साम्प्रदायिक सौहार्द आपस के भाईचारे और विश्वास का खून बुरी तरह किया गया। 30 अप्रैल 1990 को अनंतनाग जिले के निवासी स्वर्णानंद कौल प्रेमी के घर 4 बंदूकधारियों ने स्वर्णानंद कौल प्रेमी और उनके 27 वर्षीय पुत्र वीरन्द्र कौल को अपने साथ चलने के लिए विवश किया तथा जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। स्वर्णानंद कौल कवि और विद्वान थे उन्होंने भगवत गीता का कश्मीरी में अनुवाद किया था। यह तो मात्र कुछ उदाहरण हैं। ऐसे कितने लोग मारे गए जिनके नाम तथा सही संख्या अज्ञात है। *European Foundation for South Asian Studies, Amsterdam (July 2017): The Exodus of Kashmiri Pandits: EFSAS* ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कश्मीरी पंडितों के कश्मीर छोड़ने के बाद उनकी सम्पत्तियों को लूट लिया गया। उनके घरों के खिड़की-दरवाजे उखाड़ने के साथ ही बिजली की फिटिंग, उपकरण, फर्नीचर, पुस्तकें आदि लूट ली गयीं। घरों को आग लगा दी गयी। कुछ के घरों पर कब्जा कर लिया गया। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों का पुर्नवास एक कठिन समस्या है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहना उचित है कि 'द कश्मीर फाइल्स'ने कश्मीरी पंडितों के दमन, संहार और पलायन से पूरे राष्ट्र को परिचित कराने का सफल प्रयास किया है। फिल्म को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन इस दर्पण पर इतनी धूल जमने के क्या कारण थे कि



जिसे विवेक अग्निहोत्री को साफ करने में तीस सालों से भी अधिक समय लग गया और वह इतने वर्षों के बाद 1990 की कश्मीर की वास्तविकता को समाज और राष्ट्र के सामने लाने में सफल हो सके उसके लिए विवेक अग्निहोत्री की पूरी टीम प्रशंसा की पात्र है।

आज भी लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है टेलीविजन डिबेट में बैठे एक मौलाना साहब फरमा रहे थे कि कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाना ही नहीं चाहते क्योंकि सरकार यहां दिल्ली में उन्हें सारी सुविधाएं दे रही है। अपने घर को छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने का कष्ट ये ज्ञान देने वाले नहीं समझ सकते।

20 जनवरी 1990 की भयावह स्थिति का वर्णन करते हुए जम्मू काश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने अपनी पुस्तक कश्मीर— दहकते अंगारे में लिखा है कि, 'रात बिल्कुल शान्त थी, भयावह रूप से शान्त। लेकिन यह एक ऐसा मौन था, जो मेरे कानों में गरज रहा था। झील के उस पार, कुछ ही दूरी पर थी शंकराचार्य पहाड़ी, जो हमारे आन्तरिक ओज, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारी आधारभूत परम्परा का प्रतीक है। इस पूरे हिंसात्मक वातावरण में वह कितनी असहाय और उदास लग रही थी? क्या हमारे नेताओं के लिए उसकी कोई अहमियत रह गयी थी? क्या उनको यह एहसास था कि आज भारत को नयी शक्ति की जरूरत है, जो सबको जोड़ेएक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक और नैतिक दर्शन की जरूरत है जो पतन और विघटनकारी शक्तियों के सामने शंकराचार्य चट्टान की तरह खड़ा हो सके?' इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जिस शक्ति, साहस और निर्भीकता के साथ राष्ट्रहित में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया वह प्रशंसनीय है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारत की एकता, अखण्डता का प्रतीक यह निर्णय कश्मीर के लिए वरदान सिद्ध होगा और कश्मीरी पंडित पुनः सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ घर वापसी कर सकेंगे।

सन्दर्भ :

1. The Exodus of Kashmiri Pandits: *European Foundation for South Asian Studies, Amsterdam (July 2017)*
2. HETA THAKAR and VAISHNAVI MISHRA ,The Kashmiri Pandit Exodus: An Obliterated Chronicle, , International Journal of Law Management & Humanities, ISSN 2581-5369, Volume 3 | Issue 5, 2020
3. JAGMOHAN, My Frozen Turbulence In Kashmir, Allied Publihsers Limited, 1991
4. The Kashmir Files, Film, Directed by Vivek Agnihotri, 2022